

## अगस्त 2022

### PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

#### • वित्त

- बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988
- RBI का नियामक ढाँचा
- वदेशी मुद्रा प्रबंधन (वदेशी नविश) वनियम, 2022

#### • ऊर्जा

- वदियुत (संशोधन) वधियक, 2022
- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक, 2022

#### • वदेशी मामले

- सामूहिक वनिश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गेरकानूनी गतविधियाँ नषिध) संशोधन वधियक-2022

#### • पृथ्वी वजिज्ञान

- भारतीय अंतराकटकि वधियक, 2022

#### • आवासन एवं शहरी मामले

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

#### • पर्यावरण

- बैटरी अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2022
- तटीय पारसिथतिकि तंत्र का संरक्षण
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

#### • नागरिक उड्डयन

- यात्री नाम रकिॉर्ड (PNR) सूचना वनियम, 2022
- ट्रांसजेंडर पायलट आवेदकों के चकितिसकीय मूल्यांकन

### वित्त

## बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [बेनामी संपत्ति लेनदेन नषिध अधिनियम, 1988](#) के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है।

- बेनामी लेनदेन में ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जहाँ एक संपत्तिकिसी व्यक्तिके पास होती है या उसे हस्तांतरित की जाती है पर उसके लिये कसिी अन्य व्यक्तद्वारा भुगतान कयिा जाता है।
- 2016 के संशोधन से पहले अधिनियम के तहत व्यक्तियों को बेनामी लेनदेन करने से प्रतबिंधित कयिा गया था और ऐसा करने पर बेनामी संपत्तियों की ज़बती और तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था।
  - कसिी व्यक्तद्वारा अपनी पत्नी या अवविाहति बेटी के नाम पर संपत्तिकी खरीद जैसे मामलों में छूट प्रदान की गई थी।
- **बेनामी लेनदेन (नषिध) संशोधन अधिनियम 2016** ने मूल अधिनियम **बेनामी लेनदेन (नषिध) अधिनियम 1988** में संशोधन कयिा और इसका नाम बदलकर **बेनामी संपत्ति लेनदेन (नषिध) अधिनियम, 1988** कर दिया।
  - 2016 के संशोधन ने इस छूट (पत्नी या अवविाहति बेटी के नाम पर संपत्तिकी खरीद) को हटा दिया और जुर्माना बरकरार रखा।
    - इसे 1988 और 2016 के बीच कयिा गए बेनामी लेनदेन के लिये लागू माना गया था।

### सर्वोच्च न्यायालय के नयिम:

- सर्वोच्च न्यायालय ने नमिनलखिति टपिपणयिाँ की:
  - आपराधकि इरादा और बेनामी लेनदेन:

- बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की ओर से असंशोधित अधिनियम (2016 से पहले) आपराधिक इरादे से रहति था।
- हालांकि इसने एक व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियों के लिये संपत्ति के अधिग्रहण हेतु प्रतफल देने के कार्य को अपराध घोषित कर दिया।
- इसने सखत दायित्व के साथ एक कठोर प्रावधान बनाया।
- ज़बती की कार्यवाही के साथ-साथ संशोधित अधिनियम के आपराधिक प्रावधान अत्यधिक व्यापक थे और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना संचालित थे।
- इसलिये अदालत ने असंशोधित अधिनियम के तहत आपराधिक प्रावधानों और ज़बती की कार्यवाही को असंवैधानिक करार दिया।
- **बेनामी लेनदेन के लिये पूर्वव्यापी दंड:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने "1988 और 2016 के बीच बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के लिये पूर्वव्यापी सज़ा" को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसने संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन किया था।
    - अनुच्छेद 20 (1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्तियों को अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि अधिनियम के कमीशन के समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था।
  - न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले के लेनदेन के लिये आपराधिक अभियोजन या ज़बती की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है और इसे केवल संभावित रूप से लागू किया जा सकता है।

## RBI का नियामक ढाँचा

**भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने कुछ संस्थाओं द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को वनियमित करने के लिये डिजिटल ऋण देने के दिशा-निर्देशों का पहला सेट जारी किया।

- यह RBI द्वारा वनियमित संस्थाओं (जैसे कि बैंक) और ऋण सेवा प्रदाताओं (LSP) पर ध्यान केंद्रित करता है जो क्रेडिट सुविधा सेवाओं के लिये ऐसी संस्थाओं द्वारा लगाए गए हैं।

**फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:**

- **ग्राहकों का संरक्षण:**
  - सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान उधारकर्ता और वनियमित संस्था के बैंक खातों के बीच निष्पादित किये जाने हैं।
  - LSP या किसी तीसरे पक्ष के खाते में ऋण जारी या जमा नहीं किया जा सकता है।
- **भुगतान:**
  - LSP को देय किसी भी शुल्क या शुल्क का भुगतान रेगुलेटेड संस्था द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा।
- **ऋण प्रकटीकरण:**
  - उधारकर्ता को डिजिटल ऋण की सभी समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है और उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में स्वतः वृद्धि को फ्रेमवर्क के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **शिकायत नविवरण अधिकारी:**
  - बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSP के पास **फनितेक- या डिजिटल ऋण** संबंधी शिकायतों से निपटने के लिये उपयुक्त नोडल शिकायत नविवरण अधिकारी होना चाहिये।
- **डेटा प्रोटेक्शन:**
  - **डेटा संग्रह:**
    - डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिये डिजिटल लेंडिंग ऐप्स द्वारा एकत्र किये गए डेटा को ग्राहक की पूर्व सहमति से आवश्यकता-आधारित होना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इसका ऑडिट किया जा सकता है।
  - **उधारकर्ता का नियंत्रण:**
    - उधारकर्ताओं को वशिष्ट डेटा के उपयोग के लिये सहमति को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है।
    - उधारकर्ता को पहले दी गई सहमति को रद्द करने और उनके डेटा को हटाने के विकल्प भी प्रदान किये जाने चाहिये।
  - **डेटा भंडारण:**
    - सभी डेटा भारत में स्थित सर्वर में स्टोर किया जाना चाहिये।
- **रिपोर्टिंग की आवश्यकता:**
  - **क्रेडिट सूचना कंपनियों:**
    - डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों के माध्यम से प्राप्त सभी ऋणों को क्रेडिट सूचना कंपनियों (Credit Information Companies-CIC) को सूचित किया जाना चाहिये।
    - मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर रेगुलेटेड संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सभी नए डिजिटल ऋण उत्पादों, जिनमें अल्पकालिक ऋण या डेफरड भुगतान शामिल है, के संबंध में CIC को सूचित किया जाना चाहिये।

**डिजिटल ऋण:**

- इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिये तकनीक का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप के माध्यम से उधार देना शामिल है।
- बैंकों ने पारंपरिक उधार में मौजूदा कष्टताओं का लाभ उठाने के बाद डिजिटल ऋण बाज़ार में प्रवेश करने के लिये अपने स्वतंत्र डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।

## वदिशी मुद्रा प्रबंधन (वदिशी नविश) वनियिम, 2022

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने [वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियिम, 1999](#) के तहत [वदिशी मुद्रा प्रबंधन \(वदिशी नविश\) वनियिम, 2022](#) को अधसूचित कया है।

- यह वदिशी संस्थाओं में भारतीय संस्थाओं द्वारा ऋण नविश को वनियिमति करने का प्रयास करता है।

मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **भारतीय संस्थाओं द्वारा वत्तीय प्रतबिद्धताएँ:**
  - एक भारतीय इकाई कसी वदिशी संस्था द्वारा जारी कसी भी ऋण उत्पाद में उधार या नविश कर सकती है यद भारतीय इकाई:
    - वदिशी प्रत्यक्ष नविश (ODI) करने के लयि पात्र है
    - उसने वदिशी इकाई में ODI कया है
    - वत्तीय प्रतबिद्धता करते समय ऐसी वदिशी संस्था में नयित्रण हासलि कर लया है।
  - भारतीय इकाई द्वारा दयि गए ऋणों को एक ऋण समझौते द्वारा समर्थति कया जाना चाहयि जहाँ ब्याज़ दर **आर्म्स लेंथ आधार** पर ली जाएगी।
    - आर्म्स लेंथ आधार का अर्थ है, जब दो संबंधति पक्षों के बीच लेनदेन कुछ इस तरह कया जाए कहितों का टकराव न हो।
- **गारंटी देना:**
  - वनियिम भारतीय इकाई द्वारा वदिशी इकाई या उसकी कसी भी सहायक कंपनी को कुछ गारंटी देने की अनुमतति देते हैं जहाँ भारतीय इकाई ने नयित्रण हासलि कर लया है।
  - ऐसी गारंटियों में शामिल हैं:
    - भारतीय इकाई द्वारा कॉरपोरेट या प्रदर्शन गारंटी।
    - भारतीय इकाई की समूह कंपनी द्वारा कॉरपोरेट या प्रदर्शन गारंटी।
    - भारत में कसी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी।
- **रपिर्गटि की आवश्यकताएँ:** एक भारतीय नवासी जसिने कसी वदिशी संस्था में ODI, वत्तीय प्रतबिद्धता या वनिविश कया है, उसे नामति बैंकों के माध्यम से कुछ वविरणों की रपिर्गट करनी होगी। इनमें नमिनलखति शामिल हैं:
  - कया वत्तीय प्रतबिद्धता को वत्तीय प्रतबिद्धता सीमा के लयि माना जाता है।
  - वनिविश से प्राप्त होने के 30 दनों के भीतर वनिविश लेनदेन।
  - इस तरह के पुनर्गठन की तारीख से 30 दनों के भीतर पुनर्गठन।

## ऊर्जा

### वदियुत (संशोधन) वधियक, 2022

वदियुत (संशोधन) वधियक, 2022 लोकसभा में पेश कया गया। वधियक में [वदियुत अधनियिम 2003](#) में संशोधन करने का प्रयास कया गया है जो भारत में वदियुत क्षेत्र को नयित्त्रति करता है।

- इसके तहत अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर के मामलों को वनियिमति करने के लयि क्रमशः केंद्रीय एवं राज्यवदियुत नयामक आयोगों (CERC तथा SERC) के गठन का प्रावधान है।

### वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- **एक क्षेत्र में कई डसिकॉम्स:**
  - अधनियिम में प्रावधान है कएक ही क्षेत्र में आपूर्ति के लयि कई वतिरण लाइसेंसी (डसिकॉम्स) होंगे। अधनियिम में यह अपेक्षति है क डसिकॉम्स अपने नेटवर्क के जरएि बजिली का वतिरण करेंगे।
  - वधियक में यह जोड़ा गया है क डसिकॉम्स को कुछ शुल्क चुकाने पर उसी क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे नेटवर्क्स को भेदभाव रहति (नॉन-डसिक्रमिनिटरी) ओपन एक्सेस प्रदान करना होगा। केंद्र सरकार आपूर्ति के क्षेत्र के नरिधारण के लयि मानदंड नरिदषिट कर सकती है।
- **बजिली खरीद और शुल्क:**
  - एक ही क्षेत्र के लयि कई लाइसेंस देने पर मौजूदा डसिकॉम्स के मौजूदा बजिली खरीद समझौतों के अनुसार बजिली और उससे संबंधति लागत को सभी डसिकॉम्स के बीच साझा कया जाएगा।
    - अधनियिम के तहत आपूर्ति के क्षेत्र में कई डसिकॉम्स होने की स्थति में, राज्य वदियुत नयामक आयोग को शुल्क की अधिकतम सीमा नरिदषिट करनी होगी।
- **क्रॉस-सबसडि बैलेंसिग फंड:**
  - वधियक में कहा गया है कएक ही क्षेत्र के लयि कई लाइसेंस देने की स्थति में राज्य सरकार क्रॉस-सबसडि बैलेंसिग फंड बनाएगी।
    - क्रॉस-सबसडि एक उपभोक्ता श्रेणी की व्यवस्था को दूसरे उपभोक्ता श्रेणी की खपत को सबसडि देने के लयि संदरभति करती है।
    - क्रॉस-सबसडि के कारण वतिरण लाइसेंसधारी के पास कसी भी अधशिष को फंड में जमा कया जाएगा, जसिका उपयोग उसी क्षेत्र

या किसी अन्य क्षेत्र में अन्य डसिकॉम हेतु क्रॉस-सब्सिडी में घाटे को पूरा करने के लिये किया जाएगा।

### अक्षय खरीद दायित्व:

- अधिनियम SERC को डसिकॉम के लिये अक्षय खरीद दायित्वों (RPO) को नरिदषिट करने का अधिकार देता है।
- RPO अक्षय स्रोतों से बजिली का एक नश्चिति प्रतशित खरीदने के लिये जनादेश को संदर्भति करता है।
- वधियक में कहा गया है कि RPO केंद्र सरकार द्वारा नरिधारति न्यूनतम प्रतशित से कम नहीं होना चाहिये।

## ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक, 2022

[ऊर्जा संरक्षण \(संशोधन\) वधियक, 2022](#) लोकसभा में पेश किया गया और पारति किया गया।

- यह [ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001](#) में संशोधन करता है, जो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

### वधियक के मुख्य प्रस्तावों में नमिन शामिल हैं:

- **ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों के इस्तेमाल की बाधयता:**
  - अधिनियम केंद्र सरकार को ऊर्जा खपत मानकों को नरिदषिट करने का अधिकार देता है।
  - वधियक में कहा गया है कि सरकार को नामति उपभोक्ताओं को गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा खपत के न्यूनतम हसिसे को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है।
  - वभिनिन गैर-जीवाश्म स्रोतों और उपभोक्ता श्रेणियों के लिये अलग-अलग खपत सीमाएँ नरिदषिट की जा सकती हैं।
  - नरिदषिट उपभोक्ताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
    - उद्योग जैसे खनन, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, रसायन और पेट्रोरसायन।
    - रेलवे सहति परविहन क्षेत्र।
    - व्यावसायिक इमारतें, जैसा कि अनुसूची में नरिदषिट है।
  - गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग के दायित्व को पूरा करने में वफिल रहने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडति किया जा सकता है।
- **कार्बन ट्रेडिंग:**
  - वधियक केंद्र सरकार को **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम नरिदषिट** करने का अधिकार देता है।
    - कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन की एक नरिदषिट मात्रा का उत्पादन करने के लिये एक व्यापार योग्य परमटि है।
  - केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
  - संस्थाएं प्रमाणपत्र को खरीदने या बेचने के लिये अधिकृत होंगी।
    - कोई अन्य व्यक्ति भी स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीद सकता है।
- **इमारतों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहति:**
  - अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह इमारतों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहति नरिदषिट करे। संहति क्षेत्रफल के लहियाज से ऊर्जा उपभोग के मानदंड नरिदषिट करती है।
    - वधियक इसमें संशोधन करके **'ऊर्जा संरक्षण और टकिऊ भवन संहति'** का प्रावधान करता है।
    - यह नई संहति ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग और हरति भवनों की अन्य आवश्यकताओं से संबंधति नयिमें का प्रावधान करेगी।
- **आवासीय भवनों के लिये प्रयोज्यता:**
  - वधियक के तहत नया **ऊर्जा संरक्षण और टकिऊ बलिडिंग** संहति कार्यालय एवं आवासीय भवनों पर भी लागू होगा।
  - वधियक राज्य सरकारों को **लोड थ्रेसहोल्ड** को कम करने का भी अधिकार देता है।
- **वाहनों और जहाजों के लिये मानक:**
  - अधिनियम के तहत ऊर्जा खपत मानकों को उपकरण और उपकरणों के लिये नरिदषिट किया जा सकता है जो ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, संचारति या आपूर्तति करते हैं।
    - वधियक वाहनों (**मोटर वाहन अधिनियम**, 1988 के तहत परभाषति) और जहाजों (नौकाओं सहति) को शामिल करने के दायरे का वसितार करता है।
    - मानकों का पालन नहीं करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

## वदिशी मामले

### सामूहिक वनिाश के हथयार और उनकी आपूर्तति प्रणाली (गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध) संशोधन वधियक-2022

भारत सरकार ने [लोकसभा](#) में [सामूहिक वनिाश के हथयार और उनकी आपूर्तति प्रणाली \(गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध\) संशोधन वधियक-2022](#) पेश किया है।



- वर्ष 2005 का अधिनियम सामूहिक वनाश के हथियारों और उनकी वतिरण प्रणालियों के संबंध में गैरकानूनी गतविधियों को प्रतर्बिधति करने के लिये अधिनियमि कया गया था ।
- इस अधिनियम में जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों तथा उनकी वतिरण प्रणालियों से संबंधित गैरकानूनी गतविधियों को शामिल कया गया है ।

## 2022 वधियक के प्रावधान:

- सामूहिक वनाश के हथियारों से संबद्ध गतविधियों के वत्तिपोषण को प्रतर्बिधति करना ।
- इस तरह के वत्तिपोषण को रोकने के लिये केंद्र को धन, वत्तीय संपत्तया आर्थिक संसाधनों को फ्रीज करने, ज़ब्त करने या संलग्न करने का अधिकार देना ।
- सामूहिक वनाश के हथियारों और उनकी वतिरण प्रणालियों के संबंध में कसि भी नषिद्ध गतविधिके लिये धन, वत्तीय संपत्तया आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाना ।

## पृथ्वी वज्जान

### भारतीय अंटार्कटिक वधियक, 2022

भारतीय अंटार्कटिक वधियक, 2022 को लोकसभा में पारति कर दया गया है ।

- वधियक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिये पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है ।
- यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतविधियों को वनियमि करने का भी प्रयास करता है ।

वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **प्रयोज्यता:**
  - वधियक के प्रावधान कसि भी व्यक्त, जहाज़ या वमिन पर लागू होंगे जो वधियक के तहत जारी परमटि के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिये भारतीय अभियान का हसिसा है ।
  - अंटार्कटिका के क्षेत्रों में नमिनलखिति शामिल हैं:
    - अंटार्कटिका का महाद्वीप, जसिमें इसके आइस शेल्फ्स और इससे सटे महाद्वीपीय शेल्फ के सभी क्षेत्र शामिल हैं ।
    - सभी द्वीप (उनके आइस शेल्फ्स सहित) और 60 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित सभी समुद्र और वायु क्षेत्र ।
- **केंद्रीय समति की स्थापना:**
- केंद्र सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरणीय संरक्षण समति बनाएगी । समति के कार्यों में नमिनलखिति शामिल होंगे:
  - वभिन्न गतविधियों के लिये अनुमति देना ।
  - अंटार्कटिका के वातावरण के संरक्षण के लिये प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों का कार्यान्वयन और उनके अनुपालन को सुनिश्चति करना ।
  - संधि, कन्वेंशन एवं प्रोटोकॉल के पक्षों से जानकारी हासलि करना और उनकी समीक्षा करना ।
  - अंटार्कटिका में गतविधियों के लिये अन्य पक्षों से फीस/चारज पर बातचीत करना ।
- **परमटि की जरूरत:**
  - नमिनलखिति गतविधियों के लिये समति के परमटि या प्रोटोकॉल के दूसरे पक्षों (भारत के अतरिकित) से लखिति अनुमति जरूरी होगी:
    - अंटार्कटिका में भारतीय अभियान का प्रवेश या उसका वहाँ रहना ।
    - अंटार्कटिका में कसि व्यक्त का प्रवेश या भारतीय स्टेशन में रहना ।
    - भारत में पंजीकृत जहाज़ या वमिन का अंटार्कटिका में प्रवेश या वहाँ रहना ।
    - कसि व्यक्त या जहाज़ का खनजि संसाधनों को डरलि, डरेज या उसकी खुदाई करना या खनजि संसाधनों का सैपल जमा करना ।
    - ऐसी गतविधियों जो देशी प्रजातियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं ।
    - अंटार्कटिका में कसि व्यक्त, जहाज़ या वमिन का कचरा नसितारण ।

## आवासन एवं शहरी मामले

### प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)

केंद्रीय मंत्रमिडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को 31 दसिंबर, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है ।

- यह योजना पहले 31 मार्च, 2022 तक लागू थी ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) द्वारा कार्यान्वति शहरीआवास के लिये सरकार के मशिन - 2022 तक सभी के लिये आवास के अंतर्गत आती है ।

- यह शहरी गरीबों के लिये समान मासक कसितों (EMI) के पुनर्भुगतान के दौरान गृह ऋण की ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान करके गृह ऋण को

कफायती बनाता है।

## लाभार्थी:

- मशिन सलमवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/नमिन आय समूह (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संदर्भित करता है।
  - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 3,00,00 रुपए की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय के साथ।
  - नमिन आय समूह - 6,00,000 रुपए की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय के साथ) और
  - मध्यम आय समूह (MIG-I और II) जनिकी पारिवारिक वार्षिक आय 18,00,000 रुपए है।
  - लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियाँ शामिल होंगी।

## पर्यावरण

### बैटरी अपशषिट प्रबंधन नियम, 2022

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) ने अपशषिट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये बैटरी अपशषिट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया।

- ये नियम बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 का स्थान लेंगे।
- नियम इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी सहित सभी प्रकार की बैटरी को कवर करते हैं।

### वधियक की मुख्य विशेषताएँ:

- **वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव (EPR):**
  - नियम वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव (EPR) की अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं जहाँ बैटरी के नरिमाता अपशषिट बैटरियों के संग्रह और पुनरचक्रण/नवीनीकरण तथा अपशषि से प्राप्त सामग्री के नई बैटरी में उपयोग के लिये ज़मिमेदार होते हैं।
    - EPR अनविर्य करता है कि सभी अपशषिट बैटरियों को एकत्र किया जाए और पुनरचक्रण/नवीनीकरण के लिये भेजा जाए और यह लैंडफिल तथा भस्मीकरण से नपिटान को प्रतबंधित करता है।
  - EPR दायतिवों को पूरा करने के लिये उत्पादक स्वयं को संलग्न कर सकते हैं या अपशषिट बैटरियों के संग्रह, पुनरचक्रण या नवीनीकरण के लिये किसी अन्य संस्था को अधिकृत कर सकते हैं।
- **उपभोक्ताओं की ज़मिमेदारियाँ:**
  - उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिये:
    - अपशषिट बैटरियों को अन्य प्रकार के कचरे से अलग फेंकना।
    - अपशषिट बैटरियों को संग्रह, नवीनीकरण, या पुनरचक्रण में लगी इकाई को देकर उनका नपिटान करना।
- **कार्यान्वयन के लिये समति:**
  - केंद्र सरकार नियमों के कार्यान्वयन के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सफारिश करने हेतु एक समति का गठन करेगी।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) समतिकी अध्यक्षता करेगा।
- **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:**
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) बेकार बैटरी के पंजीकरण और रटिरन दाखलि करने के लिये एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा।
  - ऑनलाइन पोर्टल नरिमाता के दायतिवों को पूरा करने के लिये उत्पादकों और रीसाइकलर्स/रीफ़र्बिशर्स के बीच EPR प्रमाणपत्रों के नरिमाण और आदान-प्रदान की सुवधि प्रदान करेगा।
- **पर्यावरण कषतपूरति:** नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण कषतपूरति लगाई जाएगी।

### तटीय पारसिथतिकी तंत्र का संरक्षण

[भारत के नयितरक और महालेखा परीकषक \(CAG\)](#) ने 'तटीय पारसिथतिकी प्रणालियों के संरक्षण' पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।

CAG के नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलिखति शामिल हैं:

- **संस्थागत संरचना:**
  - तटीय पर्यावरण के संरक्षण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तदर्थ नकियाय के तौर पर राष्ट्रीय तटीय कषेत्र प्रबंधन प्राधकिरण (NCZMA) की स्थापना की थी।
    - कँग ने कहा कि तदर्थ होने और कर्मचारियों की कमी के कारण NCZMA अपना कामकाज नहीं कर पाया है।
  - इसके अतरिकित उसकी भूमिका [तटीय वनियमन कषेत्र \(CRZ\)](#) के पुनरवगीकरण पर वचिर-वमिरश करने या फ़ैसले लेने तक ही सीमति है।
  - CAG ने सुझाव दिया कि NCZMA और राज्य तटीय कषेत्र प्रबंधन प्राधकिरणों को पूरणकालिक सदस्यों के साथ स्थायी नकियाय बनाया

जाए।

#### परियोजनाओं के लिये मंजूरी:

- CRZ में गतिविधियों के लिये उद्योगों को मंजूरी लेनी पड़ती है। CAG ने कहा कि **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)** रिपोर्ट्स में कमियाँ होने के बावजूद कुछ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- इन कमियों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - गैर मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा EIA रिपोर्ट्स तैयार करना।
  - पुराने बेसलाइन डेटा का इस्तेमाल।
  - EIA में पर्यावरणीय प्रभाव का अपर्याप्त विश्लेषण।

#### परियोजना की मंजूरी से संबंधित अन्य मुद्दों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- नजी सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का सत्यापन न करना
- जन सुनवाईयों (जहाँ लोग परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में अपनी चिंताओं को जाहिर करते हैं) की कमियाँ।

#### सफ़ारिशें:

- CAG ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिये कि **परियोजना के प्रस्तावकों ने गहराई से परियोजनाओं का पारस्थिकीय मूल्यांकन** किया है।
- परियोजना के प्रस्तावक उन एजेंसियों को कहते हैं जो एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं।

#### नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखापरीक्षा

- CAG के पास सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की जाँच और रिपोर्ट करने का संवैधानिक अधिकार है।
- CAG ने 'पूर्व-लेखापरीक्षा अध्ययन' किया और पाया कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तटीय वनियमन क्षेत्र (CRZ) का उल्लंघन हुआ था।
  - उच्च ज्वार सीमा (HTL) से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और खाड़ियों, लैगून, मुहाना, बैकवाटर और नदियों के किनारे 100 मीटर के क्षेत्र को ज्वारीय उतार-चढ़ाव के अधीन तटीय वनियमन क्षेत्र (CRZ) कहा जाता है।
- मीडिया ने अवैध निर्माण गतिविधियों (समुद्र तट की जगह को कम करने) और स्थानीय नकियों, उद्योगों और जलीय कृषि फार्मों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट की घटनाओं की सूचना दी, जिससे वसितृत जाँच हुई।

## राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अद्यतन को मंजूरी दे दी है।

- वर्ष 2021 में यूके के ग्लासगो में आयोजित **UNFCCC COP 26** में भारत ने 2030 तक हासिल किये जाने वाले कुछ संशोधित लक्ष्यों की घोषणा की।
- NDC प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को शामिल करता है।
  - अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसा कि पेरिस समझौते के तहत सहमत वियक्त की गई थी।
  - इस तरह के योगदान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पार्टियों घरेलू शमन उपायों को अपनाएंगी।
- NDC हर पाँच साल में UNFCCC सचिवालय को प्रस्तुत किये जाते हैं।
  - समय के साथ महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिये पेरिस समझौता प्रदान करता है कि लगातार NDC पछिले NDC की तुलना में प्रगति का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी उच्चतम संभावित महत्त्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करेंगे।
- उत्सर्जन तीव्रता:**
  - भारत अब वर्ष 2005 के स्तर से **सकल घरेलू उत्पाद (GDP की प्रति इकाई उत्सर्जन)** की **उत्सर्जन तीव्रता** में कम-से-कम 45% की कमी के लिये प्रतिबद्ध है।
  - मौजूदा लक्ष्य 33% - 35% की कमी करना था।
- वैद्युत उत्पादन:**
  - भारत यह सुनिश्चित करने का भी वादा करता है कि वर्ष 2030 में स्थापित वैद्युत उत्पादन क्षमता का कम-से-कम 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों पर आधारित होगा।
    - यह मौजूदा 40% के लक्ष्य से अधिक है।
- अन्य NDCs:**
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाना।
  - वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन (BT) कम करना।
  - वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।

## नागरिक उड्डयन

### यात्री नाम रिकॉर्ड (PNR) सूचना वनियम, 2022

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत यात्री नाम रिकॉर्ड (PNR) सूचना वनियम, 2022 को अधिसूचित किया है।
- वनियम के अनुसार, एयरलाइंस को अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में एकत्रित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विवरण को राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्य केंद्र- यात्री (National Customs Targeting Centre - Passenger NCTCP) के साथ साझा करना होगा। NCTCP यात्रियों के

वविरण को प्रोसेस करने के लिये बोर्ड द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है।

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराधों को रोकने, पता लगाने, जाँच करने और मुकदमा चलाने के लिये वविरण एकत्र किये जाते हैं।

**वनिधियों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:**

- साझा कथिा जाने वाले वविरण:**
  - एयरलाइंस को यात्री वविरण जैसे नाम, **PNR रकिॉर्ड, टकिट आरक्षण की तारीख, यात्रा की तारीख, सभी संपर्क जानकारी और सामान की जानकारी** NCTCP के साथ साझा करनी होगी।
- सूचना साझा करना:**
  - NCTCP अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सरकारी वभिागों के साथ अनुरोध पर यात्री वविरण साझा कर सकता है, अगर वे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के संबंध में आवश्यक हैं।
- सूचना का संरक्षण:**
  - NCTCP द्वारा एकत्र की गई जानकारी को केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा संरक्षित, प्रोसेस और प्रसारित कथिा जाएगा।
  - किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, राजनीतिक राय, ट्रेड यूनियन सदस्यता, स्वास्थ्य या यौन अभिविन्यास जैसे वविरण प्रकट करने की अनुमति नहीं है।
- डेटा का प्रतधिरण:**
  - वविरण पाँच साल तक रखे जाएंगे, जब तक कि वे जाँच, अभियोजन या अदालती कार्यवाही के लिये आवश्यक न हों।
  - वविरण पाँच साल बाद गुमनाम कर दिया जाएगा।
  - किसी पहचान योग्य मामले, खतरे या जोखिम के संबंध में आगे के वशि्लेषण के लिये ज़रूरी होने पर वविरण एक अधिकृत अधिकारी द्वारा 'प्रतरूपित' कथिा जा सकता है।

## ट्रांसजेंडर पायलट आवेदकों के चकित्सकीय मूल्यांकन

नागर वभिानन महानदिशालय (DGCA) ने ट्रांसजेंडर पायलट आवेदकों के चकित्सकीय मूल्यांकन करने के लिये मेडिकल परीक्षकों हेतु दशिा-नरिदेश जारी कथि।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो जन्म के समय अपने नरिदषिट लिंग से सामाजिक संक्रमण से गुजरते हैं।

**दशिानरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:**

- पंजीकरण प्रक्रथिा:**
  - प्रारंभिक चकित्सकीय जाँच कराने वाले ट्रांसजेंडर आवेदक अपने सर्टफिकेट ऑफ आइडेंटिटी पर लखिति जेंडर के अनुसार नागरकि उड्डयन के ई-गवर्नेंस पोर्टल (eGCA) पर पंजीकरण करेंगे।
  - ऐसे उम्मीदवारों को भारतीय वायुसेना के एयरोस्पेस मेडसिनि संस्थान (IAM) में आगे की जाँच के लिये चकित्सा आकलनकरत्ताओं द्वारा अस्थायी रूप से अनफटि घोषित कथिा जाएगा।
- आकलन के लिये दशिानरिदेश:**
  - IAM में आवेदकों को वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (WPATH) मानकों के अनुसार मनोचकित्सक या मनोवैज्ञानिक द्वारा एक वसितृत मानसकि स्वास्थ्य परीक्षा से गुजरना होगा।

**तालकिा 2: ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिये चकित्सकीय आकलन के मानदंड**

स्थिति	आकलन
कम-से-कम पाँच साल पहले जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी या हार्मोन थेरेपी से गुजरना।	यदि कोई मनोरोग संबंधी असामान्यता नहीं है, और हार्मोन थेरेपी के कोई डॉक्यूमेंटेड दुष्परभाव नहीं हैं, तो आवेदक को फटि माना जाएगा।
जेंडर रीअसाइनमेंट या हार्मोन थेरेपी हुए पाँच साल पूरे नहीं हुए या मानसकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या उपचारों का इतिहास रहा हो।	जेंडर रीअसाइनमेंट या हार्मोन रपिलेसमेंट थेरेपी के लिये सर्जरी कराने वाले आवेदकों को प्रक्रथिा के बाद तीन महीने के लिये चकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।